हिन्दुस्तान

# खास

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

प्रदेश सरकार यूपी से निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकों को कई सहूलियतें देगी। साथ ही उन देशों पर निगाह रखे है जो चीन से माल आयात कम करने की तैयारी में हैं। ऐसे देशों को निर्यात बढ़ाने की कोशिशें तेज हो गईं हैं।

उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को

**05** स्थान है निर्यात में यूपी का देश में। सर्वाधिक 41 फीसदी मीट निर्यात

**4.9** प्रतिशत है देश के निर्यात में यूपी का योगदान

सिस्टम बनाएगी। यही नहीं उनके लिए जीएसटी रिफंड संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए जल्द जीएसटी सेल बनेगा। एमएसएमई विभाग ने इन प्रावधानों को अपनी नई निर्यात नीति में खास तौर पर जोड़ा है। यह निर्यात

सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की तैयारी कर रही है। उसके इसके लिए प्राइसवाटर कूपर सलाहकार कंपनी की सेवाएं लीं हैं। उन क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने को फोकस किया जाएगा जहां बढ़ोतरी की व्यापक संभावनाएं हैं।

## खास बातें

- निर्यात योग्य उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक पंजीयन कराया जाएगा
- यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम (टीआईईएस) की तर्ज पर योजना शुरू की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त फ्लैटेड इंडस्ट्रियल पार्क में स्थापित निर्यातक इकाईयों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो प्रदान किया जाएगा
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला निर्यात बंधु का गठन
- यूपी में केंद्र की योजना की तर्ज पर निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोल्ड चेन, बार्डर हाट, लैंड कस्टम स्टेशन, ड्राई पोर्ट, प्रामाणीकरण लैब, निर्यात पार्क, हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल, व्यापार प्रोत्साहन केंद्र, व पैकेजिंग केंद्र बनाए जाएंगे
- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पूर्णकालिक पदों का सृजन होगा